ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा: एक परिदृश्य
Current Indian Higher Education: A Scenario

Paper Submission: 11/11/2021, Date of Acceptance:22/11/2021, Date of Publication: 23/11//2021

अवधेश कुमार झा
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग,
हे० न० ब० राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नैनी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, प्रबंधन, भाषा संगीत आदि में स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक की डिग्री के साथ साथ डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान करता है। भारत में, विशेष तौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 35,900,000 छात्र/छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी उच्च शिक्षा का विस्तार ग्रामों तक संभव हो पाया। वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक से अधिक स्वतंत्र प्रदान की जाये क्योंकि राजनैतिक हस्तक्षेप एवं अधिकाधिक नियंत्रण के कारण इसका स्वरुप बिगड़ता जा रहा है।

Education is a medium that provides degrees from undergraduate to postgraduate level as well as doctoral degrees in various fields such as arts, management, language music, etc. There are about 35,900,000 students studying in India, especially in higher educational institutions.The extension of higher education to the villages was also possible through distance education. At present, there is a need that higher educational institutions should be provided more and more independent because due to political interference and more and more control, its form is deteriorating.

मुख्यशब्द: रचनात्मक, विकसित प्रणाली, दुरस्त शिक्षा, योजना, वैश्विक परामर्श, मुद्रास्फीति, बेरोजगार, विषय आधारित, इक्विटी, उत्कृष्टता, निगरानी, प्रोद्योगिकी, अभिवृति, अनुसन्धान, बहुलता, पारदर्शिता, अलगाव, मूलभूत संसाधन, असमानता, डिजिटल सामग्री, प्रशिक्षण, निरिक्षण, विचार-कौशल, रुदिवादी दृष्टिकोण, संरक्षणवाद, वित्तपोषण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, रोज़गार, समावेशी ।

Keywords: Creative, Developed Systems, Dynamic Education, Planning, Global Consultation, Inflation, Jobless, Subject-Based, Equity, Excellence, Monitoring, Technology, Attitude, Research, Plurality, Transparency, Isolation, Basic Resources, Inequality, Digital Content, Training, Observation, Thought, Conservative Approach, Protectionism, Financing, Internationalization, Employment, Inclusive.

प्रस्तावना

वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा जो रचानात्मक एवं बौद्धिक रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रहा है एक अत्यधिक विकसित प्रणाली है जो विभिन्न क्षेत्रों में यथा-कला, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून, संगीत प्रदर्शन-कला, राष्ट्रीय एवं विदेशी भाषाओं, सांस्कृतिक शिक्षा, कला, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, मानविकी आदि में स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर एवं डाक्टरेट की डिग्री अथवा डिप्लोमा दे रहे हैं, अगर देखा जाये तो वर्तमान में नामांकन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व के तीसरे स्थान पर है।

भारत में इस समय कुल 1019 विश्वविद्यालय,54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय ,442 राज्य विश्वविद्यालय, 397 निजी विश्वविद्यालय, 126 डीम्ड विश्वविद्यालय और 5 संस्थानों राज्य कानून, राष्ट्रीय महत्व के 30 संस्थानों के माध्यम से स्थापित 45 तकनीकी संस्थानों, 13 प्रबन्ध संस्थानों, 4 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, 6 विज्ञान और अनुसंधान और 3 योजना-निर्माण व वास्तुकला संस्थान हैं। 25,900,000 छात्रों ने भारत में 45,000 से अधिक डिग्री और डिप्लोमा संस्थानों में दाखिला लिया है। इन संस्थानों की स्थापना दो तिहाई निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की गयी है और जिसमें से 4.2 लाख छात्र दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामंकित हैं। विश्व औसत 27% की औसत चीन(26%) और ब्राजील (36%) के मुकाबले भारत की 16% की औसत काफी कम है।

भारत सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 35,9000,000 छात्रों के नामांकन प्राप्त करने का इरादा रखती है और 12वीं योजना अवधि के अंत तक 25.2% की प्राप्त करने का एकाधिक प्रकार के संस्थानों सहित जिनमें अनुसंधान केंद्रित, शिक्षा और व्यवसाय केंद्रित भी शामिल हैं के माध्यम से प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। 2020 तक सकल नामांकन अनुपात के दुगुना करने के लिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है। वैश्विक परामर्श फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का 15% के मौजूदा स्तर से 2020 तक का प्रति 30% प्राप्त करना है। कुल छात्र नामांकनके अनुपात के संदर्भ में भारत में कुल लगभग 75% छात्र स्नातक डिग्री स्तर पर नामांकित है जो 43% चीन के और उसके आधे अमेरिका की तलुना में है। स्नातक स्तर पर यह धनत्व न केवल आटर्स, साइंस और कॉमर्स में तीन साल की डिग्री के कारण भारत के लिए अद्वितीय है और जो स्नातक

नामांकल की दृष्टि से 85% से अधिक है और इसका कारण हो सकता है यहाँ की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति जिसमें यह विचारधारणायें समाहित है कि स्नातक डिग्री प्राप्त कर लेने के पश्चात ऊर्ध्वाधर रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रश्स्त होता है। स्नातक स्तर की इस घनत्व का शिक्षा के सभी क्षेत्रों में यथा-व्यावसायिक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट आदि प्रमुख स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। स्नातक डिग्री धारकों की इतनी व्यापक उपलब्धता एक छोटे से अर्थव्यवस्था के लिए जो चीन या अमेरिका की तुलना में, क्रेडेंशियल मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा कर दी है जिसका तात्पर्य है कि इस समय साक्ष्य कई बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार कॉलेज स्नातकों की अधिकता से स्पष्ट हैं, परिणाम शिक्षा की खराब गुणवत्ता और कई संस्थानों में दिये गये कौशल को दर्शाता है। व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें से कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की ओर रूख कर लेते हैं ताकि मनोवांछित व्यवसाय की प्राप्ति हो सके, जिसके परिणामस्वरूप स्नातकोत्तर स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व को देखा जा सकता है।

चीन की तुलना मे भारत जनसंख्या को छोटे आकार होने और उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार के कारण स्नातकोत्तर स्तर पर (27लाख बनाम 12लाख) छात्रों की संख्या में दोगुने से भी अधिक है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तो वह भारत के काफी आगे है, अनुमान सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से लगाया जा सकता है, जो 69 लाख छात्रों की तुलना में सिर्फ 40 लाख छात्रों पर ही है, सबसे विकट समस्या भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की है, एक ओर तो उनकी उस मात्रा में उपलब्धता की कमी तथा दूसरी ओर उच्च श्रेणी की विषयधारित, विषय-क्षेत्र-आधारित अनुसंधानोन्मुखी शिक्षकों की कमी, क्योंकि अनुसंधान किसी भी क्षेत्र के लिए आलोचना और समस्या को सुलझाने की नींव के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। दूसरे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी कम सकल नामांकन अनुपात(जीईआर) के रूप में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है तथा इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार,हमारी जनसंख्या का 26% अभी अनपढ़ है। अन्य प्रमुख मुद्दे जैसे समानता, उत्कृष्टता, शासन द्वारा वित्त पोषण, कार्यान्वयन और निगरानी, प्रशासन और वितरण की गुणवत्ता में सुधार। उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च बहुत कम किया गया है, इससे महत्वपूर्ण विस्तार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। उच्च शिक्षा संस्थानों मे आई.सी.टी. अवसंरचनाओं की कमी तथा निम्न प्रौद्योगिकी के प्रति रूझान व कार्यरत व्यक्तियों की तत्परता एवं अभिवृत्ति, डिजीटल सामग्रियों का क्षेत्रीय भाषाओं में निम्म स्तरीय उपलब्धता भी अहम हैं। अनुसंधानों के लिए सीमित धन की उपलब्धता और साथ ही साथ शैक्षिक संस्थानों का उद्योग और सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं से निम्नस्तरीय संबंध, व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण का शिक्षा की मुख्यधारा से अलगाव अप्रासंगिकता भी उत्तरदायी है। अतिव्यापी भूमिकाओं के साथ नियामकों की बहुलता, असमानता, प्रविष्टि अवरोधों के कराण एक विषम प्रणाली का विकास सीमित पारदर्शिता, निम्न स्वायत्तता और खराब गुणवत्ता युक्त नियंत्रण प्रणाली भी जिम्मेदार है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राजनैतिक हस्तक्षेप एवं अधिकाधिक नियंत्रण के कारण स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, परिणाम कुलपतियों का चयन हो या टॉप फैक्ल्टी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जाना, अधिकाधिक रूपों में आवश्यक मूलभूत संसाधनों की प्रतिपूर्ति करना ताकि संस्थान विश्वस्तरीय बन सकें। पाठ्यक्रमों का समयानुकूल परिवर्तन एवं क्षेत्रीय, भौगोलिक आधार पर तथा औद्योगिक आधार पर क्रियाकौशलों से सम्बद्ध किया जाना। सेमेस्टर प्रणाली, विकल्प आधारित क्रेडित प्रणाली और परीक्षा सुधारों की शुरूआत की जरूरत है। अंतर-राज्य असमानता (दिल्ली में 47.9% बनाम असम में 9%) भी एक बड़ी चुनौती है। शहरी-ग्रामीण असमानता-शहरी क्षेत्रों में 30% बनाम ग्रामीण क्षेत्रों में 11.1% । समुदायों में भी अंतर एक बड़ा कारण है जो इस प्रकार है –ओबीसे के लिए 14.8%अनुसूचित जातियों के लिए 11.6% अनुसूचित जनजाति के लिए 7.7% और मुसलमानों के लिए 9.6% की स्थिति तथा लिंग असमानत-महिलओं के लिए 15.2% बनाम पूरूषों के लिए 19% है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपलब्धि की कामना की जा सकती है – ज्ञान नेटवर्क के सृजन के माध्यम से, अनुसंधान और नवाचार केन्द्रों, कॉर्पोरेट समर्थित संस्थानों, शिक्षकों के विकास के लिए समर्थन के रूप में सरकार द्वारा प्रदर्शन आधारित वित्त पोषण किया जाना चाहिए। पीपीपी मॉडल के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में अईसीटी आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने एवं सुधार तथा अध्यापन से आईसीटी के प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की सामग्री तंत्रों का विकास व मुफ्त वितरण, उच्च शिक्षा संस्थानों में कनेक्टिविटी में सुधार एवं डिजिटल सामग्री के राष्ट्रीय भंडारण की ईकाई का गठन करने की जरूरत है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए निरीक्षण संरचना में सुधार तथा सुविधाजनक बनाने हेतु अधिक से अधिक उद्योग की भागीदारी बाजार की जरूरत के साथ उनका संरक्षण आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान स्तर का अवलोकन।
2. भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास।
3. उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी का परस्पर सम्बन्ध और इसमें सुधार।
4. उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतर तकनीकों का प्रयोग।
5. शिक्षण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व।
6. रोज़गार परक उच्च शिक्षा की आवश्यकता।

निष्कर्ष

एक उचित नियामक तंत्र के साथ विदेशी संस्थानों का भारत में प्रवेश बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भारत को अधिकाधिक संस्थानों को खोलने के साथ-साथ विदेशी संस्थानों के साथ भी सहयोग प्राप्त करना और विश्व समुदाय के साथ मिलकर प्रयोग भी करना चाहिए। संकाय में देशी –विदेशी शिक्षकों और अन्य देशों छात्रों के आने से विचारों के आदान-प्रदान द्वारा विभिन्न विचार-कौशलों द्वारा प्रसार हो सकता है। इससे लाभ यह होगा कि, रूढ़ीवादी दृष्टिकोण, संरक्षणवाद और कम नौकरी के अवसरों के चलते वर्तमान वैश्विक सीमा में हमारे युवाओं के आजीविका की संभावनाओं को नुकसान नहीं होगा। योग्यता के आधार पर छात्र वित्तपोषण, शिक्षा का अंतराष्ट्रीयकरण, शिक्षा वितरण के लिए बेहतर तकनीक का प्रयोग और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनेगा।

सन्दर्भ

1. *Ananda Krishnan, M (2004). Power Initiatives in higher education, Sneh Prakashan and Amity Foundation for learning, New Delhi. pp. 202-25.*
2. *Bachhi, C (2001). Managing equity: Mainstreaming and diversity in Australian Universities. In A Brooks and A MeInnon (eds). pp. 119-35.*
3. *Bal, (2004). Women scientists in India: Nowhere near the glass Ceilingin Economic and Political Weekly, August 7th, pp.3647-53.*
4. *Chanana, K (1988). Social change or social reform: the education of women in Pre independence India in K. Chanana (ed), Socialisation, Education and Women: Explorations in gender identity*
5. *Chanana, K (2003). Visibility, Gender and the Careers of Women Faculty in an Indian University in MeGill J. Educ. 38(3):381-90*
6. *Economic And Political Weekly (2007), Vol. XLII, No.7 February, 17-23. A Sameeksha Trust Publication. Mumbai.*
7. *Marginson, S (2000). Research as a Managed economy: Why Universitiies matter: A conversation about values, means and directions. Allen and Unwin, Sydney.*
8. *Sassen, S (1998). Globalisation and its discontents: essays on the new mobility of people and money. The New Press, N*ew York.
9. Sharpe, R (1976). Just like a girl. Pelican, London.